Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

जुलाई 2023 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **4**

- डीग में स्थापित होगा संग्रहालय 4
- राज्यपाल ने किया दिव्य कला मेले का उद्घाटन 4
- राजस्थान 4
- राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय 5
- प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष में विभिन्न योजनाओं के तहत 231 करोड़ रुपए स्वीकृत 6
- भरतपुर एवं बीकानेर में बनेंगे मल्टीपरपज इंडोर हॉल 6
- पुलिस अकादमी में 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वूमेन'की शुरुआत 7
- मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का किया गया गठन 8
- प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 8
- मुख्यमंत्री ने किया 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'के प्रारूप का अनुमोदन 9
- बरवास माईक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास 9
- मद्यसंयम के लिये चलेगा गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान 10
- प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये बनेंगे 5 नवीन छात्रावास 11
- होमगार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिये समिति का होगा गठन 11
- प्रदेश के 10 महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत 11
- प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया 12
- मुख्यमंत्री ने किया टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन 13
- जनसंपर्क अलंकरण समारोह 14
- फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना के लिये मिलेगा अनुदान 14
- जयपुर में बनेगा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय 15
- जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट-सवाई माधोपुर के गजेंद्र को मिला एक लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार 15
- विभिन्न ज़िलों में बनेंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास- जयपुर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और जोधपुर में नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा 16
- राइट-टू-हेल्थ कानून के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित 16
- राज्यस्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार 16
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 18
- प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय 18
- प्रदेश में 50 पक्षीघरों का होगा निर्माण 18
- राज्य स्तरीय सेमिनार राज. पल्मोकोन 2023 19
- केंद्रीय कारागार अलवर में 'दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन'का कारागार मंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन 20
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट-2023 : पर्यटन मंत्री ने किया आरडीटीएम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 20
- प्रदेश में 11 मिलेट्स एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये 3 करोड़ 37 लाख रुपए का अनुदान 21
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 22

नोट :

- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 22
- प्रदेश के 36 विद्यालयों में 45 नवीन विषय होंगे प्रारंभ 23
- राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 24
- राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 पारित 24
- राज्य में अब 19 ज़िलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड की सूची जारी 25
- राजस्थान कारागार विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 26
- राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित 27
- मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 27
- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 28
- तीन दशक में सर्वाधिक बैठकें पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में 28
- राजकीय महाविद्यालयों में मिलेगी कैंपस प्लेसमेंट सुविधा 28
- राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 ध्वनिमत से पारित 29
- राज्यपाल ने एपिलेप्सी पर इकोन-2023 सम्मेलन का किया उद्घाटन 30
- राजस्थान युवा महोत्सव-2023 30
- राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर ने वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के बकाया पुरस्कारों की घोषणा की 31
- राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिये विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना 33
- राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का हुआ गठन 34
- राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित 34
- राजस्थान स्टेट गैस ने लागू की स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण नीति 34
- जेजेएम में अब तक 5.40 लाख एफएचटीसी जल कनेक्शन में चौथे एवं व्यय में दूसरे स्थान पर राजस्थान 35
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ 36
- राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन 37
- प्रदेश के 246 राजकीय विद्यालय होंगे अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित 38
- प्रदेश में 3 उपखंड, 7 तहसील और 20 नवीन उप तहसीलों का होगा गठन 38
- राज्यपाल ने राज्य सरकार के अधिसूचना प्रस्तावों को दी मंजूरी 38
- प्रदेश के 28 ज़िलों में खुलेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल 39
- कोटा में तैयार हुआ दुनिया का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 39
- प्रदेश में 15 अल्पसंख्यक राजकीय आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण 41
- प्रधानमंत्री ने सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की 41
- प्रधानमंत्री ने राजस्थान में छह ईएमआरएस का उद्घाटन किया 43
- राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन 44
- नेवटा बांध और कानोता बांध बनेगा ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट 44
- 'प्रसव वॉच'एप्लीकेशन को मिला 'नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवॉर्ड' 45
- देवस्थान विभाग व आईआरसीटीसी के बीच हुआ एमओयू 46
- 'मिशन वात्सल्य योजना'का अनुमोदन 46
- लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड 47
- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघिन टी-111 के तीन शावकों का हुआ नामकरण 47
- जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में आरती, मनीष और किरण ने जीते नकद पुरस्कार 48
- राजस्थान को मिला बेस्ट कल्चरल टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवॉर्ड 48

नोट :

राजस्थान

डीग में स्थापित होगा संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भरतपुर ज़िले के डीग में संग्रहालय स्थापित करने के लिये 4.21 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, भरतपुर राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित करती गैलेरी, महाराजा सूरजमल गैलेरी, आर्म्स गैलेरी, मूर्ति गैलेरी, उत्खनन गैलेरी, कला एवं संस्कृति गैलेरी, ब्रजमंडल गैलेरी, पेंटिंग गैलेरी सहित कुल 8 गैलेरी का निर्माण किया जाएगा।
- साथ ही, डीग किला क्षेत्र में मुख्य द्वार से संग्रहालय भवन तक हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट, जल आपूर्ति संबंधी कार्य, पर्यटकों की सुविधा के लिये आवागमन तथा अन्य विकास कार्य भी करवाए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पर्यटकों को डीग किले के साथ-साथ भरतपुर के राजवंश, ब्रज की कला एवं संस्कृति, प्राचीनकाल के हथियारों सहित विभिन्न जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल सकेंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

राज्यपाल ने किया दिव्य कला मेले का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्यांगजनों के उत्पादों की वृहद स्तर पर ब्रांडिंग कर उनके हुनर और शिल्प कौशल को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने दिव्य कला मेले में कहा कि दिव्यांगजनों के हुनर और उनके कौशल को जनता तक पहुँचाने की दिशा में इस तरह के मेलों की बहुत सार्थकता है। इन आयोजनों से दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास का सृजन होता है और उनके आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलता है।
- ये मेले दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये ही नहीं, भारतीय कला और शिल्प के प्रसार की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। बाज़ारवाद और विज्ञापन के दौर में ऐसे मेले कला और संस्कृति से जुड़ी मन की अभिव्यक्ति को उत्पाद के रूप में सामने लाते हैं।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश में अलग- अलग राज्यों में दिव्य कला मेलों का आयोजन कर वहाँ के दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को मंच प्रदान किया जा रहा है।
- विदित है कि देश में 13 हज़ार शिविरों का आयोजन कर 25 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गए हैं। समाज से इन आयोजनों को मिल रहे समर्थन से दिव्यांगजनों में नई आशा और स्वावलंबन की भावना का संचार हो रहा है।
- दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये भारत सरकार ने विशेष पहल की है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके हुनर को निखारकर उन्हें मुख्यधारा में लाने का कार्य किया जा रहा है।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने दिव्यांग स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को स्वरोज़गार शुरू करने के लिये रियायती ऋण की स्वीकृतियाँ, ट्राइसाइकिल, हियरिंग एड, वाकिंग स्टिक आदि सहायक उपकरण भी वितरित किये।

नोट :

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवीन ज़िलों के गठन पर चर्चा, विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हित में प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन ज़िलों के गठन के लिये बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इन नवीन ज़िलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी। विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से होगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।
- विदित है कि इस बार के बजट में 19 ज़िलों की घोषणा की गई थी। इस क्रम में रामलुभाया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट द्वारा आंकलन कर सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई।
- मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
  - इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता पर विश्वास तथा गर्व और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार 'नो बैग डे' किया जाएगा।
  - नई प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने 'दी राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट) बिल-2023' के प्रारूप को मंज़ूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम 'दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' करने का निर्णय लिया है।
  - इससे कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लिये ऑर्डिनेंस लाने आदि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
  - इस निर्णय से विश्वविद्यालय का कार्य सुगमता और त्वरित गति से हो सकेगा। मंत्रिमण्डल की इस स्वीकृति से यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी।

नोट :

- साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियाँ (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे।

- मंत्रिमंडल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक-से-अधिक नियोजित करने और शीघ्रलिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
  - इसके अंतर्गत शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान किया गया है।
  - साथ ही, फेज-II के लिये विज्ञापित पदों में 15 गुणा विद्यार्थियों को सम्मिलित करने तथा शीघ्रलिपि को वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी किये गए हैं।
- मंत्रिमंडल ने महिला राजकीय कार्मिकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिये राजस्थान सिविल सर्विसेज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूल्स, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
  - उक्त संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी, जिसको राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम-1999) में परिशिष्ट 'च' में संशोधन कर इनमें 'उद्योग विभाग' का नाम 'उद्योग एवं वाणिज्य विभाग' करने का निर्णय लिया है। नाम परिवर्तन होने से विभाग के अधिकारियों का पदनाम भी संशोधित हो जाएगा।

प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष में विभिन्न योजनाओं के तहत 231 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2023 को राजथान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 231.44 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति दी। यह राशि एमबीसी विकास कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 'देवनारायण अनुप्रति योजना' के लिये 1.50 करोड़ रुपए, 'देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति' के लिये 8 करोड़ रुपए, 'देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति' के लिये 135 करोड़ रुपए, 'देवनारायण गुरूकुल योजना' के लिये 17.50 करोड़ एवं 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना' के लिये 20.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा एवं जयपुर के विराटनगर में देवनारायण आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 37.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- इनके अलावा अलवर के उमरेण, टोंक के निवाई तथा जयपुर में मानसरोवर व प्रतापनगर में देवनारायण छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये 11.20 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी तथा वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में एमबीसी विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया गया है।

भरतपुर एवं बीकानेर में बनेंगे मल्टीपरपज इंडोर हॉल

चर्चा में क्यों ?

2 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भरतपुर एवं बीकानेर ज़िलों में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण करने के लिये 16.44 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रत्येक हॉल के निर्माण में 8.22 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- मल्टीपरपज इंडोर हॉल के निर्माण से खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स में भाग लेने तथा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे।
- उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी।

पुलिस अकादमी में 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वूमेन'की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2023 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक श्रुति भारद्वाज ने स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला फिजिकल टीचर्स (पीटीआई) के लिये 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कोर्स 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वूमेन'का शास्त्री नगर के राजस्थान पुलिस अकादमी में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा के लिये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिये 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया है।
- इस अवसर पर श्रुति भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक प्रदेश में 20 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य स्तर पर इस विशेष ट्रेनिंग में ज़िलों से शामिल महिला ट्रेनर्स को आत्मरक्षा की बारीकियाँ सिखाई जाएंगी, इसके बाद वे आगे चलकर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी।
- इसके साथ ही इस वूमन पीटीआई को महिला अधिकारों और कानूनों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी ताकि वे बालिकाओं को अपने अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक कर सकें।

नोट :

मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का किया गया गठन

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम-2018 के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इसके लिये गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक जनस्वास्थ्य को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। साथ ही इस प्राधिकरण में इनके अलावा पदेन एवं गैर सरकारी सदस्य भी होंगे।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि शीघ्र ही मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक आयोजित कर राज्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियम और उपनियम बनाए जाएंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड भी गठित किये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि बैठक में मानसिक रोगियों के अधिकारों संबंधी नियमावली भी निर्धारित की जाएगी।

प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- नितिन गडकरी ने राजस्थान में कुल 219 किमी. लंबाई और 3,775 करोड़ रुपए की लागत वाली चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा खंड तक इस 6-लेन की परियोजना से अजमेर और भीलवाड़ा ज़िलों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।
- गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ खंड को 6-लेन का बनाने से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ज़िलों के उदयपुर, जयपुर और कोटा क्षेत्र का परस्पर संपर्क मज़बूत होगा।
- फतहनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 162ए पर 4-लेन आरओबी के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
- नितिन गडकरी ने सीआरआईएफ के तहत मंडरायल में चंबल नदी पर ऊँचाई वाले पुल (या हाई लेवल ब्रिज) के निर्माण का शुभारंभ किया। इस पुल के निर्माण से राजस्थान के मंडरायल, करौली और मध्य प्रदेश के सबलगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1850 करोड़ रुपए लागत वाली और कुल 221 किमी. लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
- ये परियोजनाएँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा से उदयपुर हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क उपलब्ध कराएंगी।
- प्रतापगढ़ बाईपास के निर्माण से शहर के अंदर यातायात का बोझ कम होगा।
- रास से ब्यावर तक सड़क बनने से भीलवाड़ा की ओर जाने वाले वाहनों को सुविधा होगी।
- डूंगरपुर, उदयपुर और बाँसवाड़ा क्षेत्र के जनजातीय इलाकों को बेहतर संपर्क उपलब्ध होगा।
- सांगवाड़ा और गढ़ी में बाइपास बनने से डूंगरपुर-बाँसवाड़ा की दूरी 10 किमी. कम हो जाएगी।

नोट :

- ब्यावर-गोमती मार्ग पर टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये 13 एनिमल अंडरपास बनाए जाएंगे।
- इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में सीआरएफ के तहत 2250 करोड़ रुपए की लागत से 74 परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा भी की गई। इन परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'के प्रारूप का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को प्रदेश में रोज़गार को बढ़ावा देने के क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'के प्रारूप को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोज़गार के लिये आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिये 5-5 हज़ार रुपए की सहायता मिलेगी।
- इनमें राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से संचालित हस्तशिल्प योजना, राजीविका/एनयूएलएम-महिलाएँ तथा श्रम विभाग-कामगार द्वारा चिह्नित दस्तकार शामिल होंगे।
- इस निर्णय से इन वर्गों के लोगों को स्वरोज़गार के लिये बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'शुरू करने की घोषणा की थी।

बरवास माईक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2023 को राजस्थान के युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना ने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बूंदी ज़िले के बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बूंदी ज़िले के बरवास गाँव में परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को फसल बुवाई में विकल्प मिलेंगे और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ काश्तकारों को मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य बजट में हिंडोली-नैनवाँ क्षेत्र के लिये कई घोषणाएँ की गई हैं। बीते चार सालों में इस क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सड़क सहित कई क्षेत्रों में विकास कार्य हुआ है।
- राज्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बनाए गए मिनी डेम और एनीकटों से किसानों को सिंचाई तथा ग्रामीणों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। साथ ही, क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इन कार्यों पर 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

मद्यसंयम के लिये चलेगा गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिये राज्य सरकार स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 3 माह की कार्ययोजना के लिये 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ तथा सिविल सोसायटी के माध्यम से प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता फैलाई जाएगी।

नोट :

- साथ ही, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी मद्यसंयम कार्यशालाएँ आयोजित होंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये बनेंगे 5 नवीन छात्रावास

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु 5 नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु नवीन भवनों का निर्माण प्रदेश के अलवर ज़िले के मालाखेड़ा, श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़, पाली ज़िले के रायपुर व उदयपुर ज़िले के कानोड़ में सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास तथा चूरू ज़िले के जैतासर में डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिये किया जाएगा।
- प्रत्येक छात्रावास के लिये 2.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन छात्रावासों में 50-50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता होगी।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अनुसूचित जाति के विद्यार्थी सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

होमगार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिये समिति का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएँ देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।
- महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा तथा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- यह समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों का 12 माह नियोजन किये जाने, मानदेय पुलिस आरक्षी के समान दिए जाने, महँगाई भत्ता व ईएसआई/पीएफ सुविधा दिये जाने तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण संबंधी कार्य करेगी।
- समिति गठन के अलावा, राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किये जाने की स्वीकृति भी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने मई 2023 में जयपुर स्थित नवनिर्मित होमगार्ड मुख्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान यह घोषणा की थी।

प्रदेश के 10 महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नवीन विषय शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय महाविद्यालय देशनोक बीकानेर, राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला बीकानेर, वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर, राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ धौलपुर, राजकीय

नोट :

महाविद्यालय मांगरोल बारां, राजकीय महाविद्यालय उच्चौन भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना नागौर, राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन पाली तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपलू टोंक में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय शुरू किये जाएंगे।

- इन विषयों के संचालन के लिये सहायक आचार्य के 20 तथा प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पदों सहित कुल 26 पदों का सृजन होगा।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा और विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय का अध्ययन नजदीक ही करने के अवसर मिलेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसके संबंध में घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

8 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें शामिल हैं- अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह-लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड; हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन का चरण-I बीकानेर पावर ग्रिड द्वारा विकसित भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल।
- प्रधानमंत्री ने अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड राष्ट्र को समर्पित किया।
  - 500 किमी. से अधिक लंबा यह खंड, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले के जाखड़ावाली गाँव से जालौर ज़िले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।
  - एक्सप्रेसवे यात्रा-अवधि को काफी कम कर देगा और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच परिवहन-संपर्क में सुधार करेगा।
  - एक्सप्रेसवे न केवल माल के निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि अपने मार्ग पर पर्यटन और आर्थिक विकास में भी वृद्धि करेगा।
- क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिये अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण-I का लोकार्पण किया, जिसे लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।
  - हरित ऊर्जा गलियारा लगभग 6 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा और पश्चिमी क्षेत्र में ताप-विद्युत उत्पादन और उत्तरी क्षेत्र में जल-विद्युत उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड संतुलन में मदद करेगा, जिससे उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच ट्रांसमिशन क्षमता मज़बूत होगी।
- प्रधानमंत्री ने लगभग 1,340 करोड़ रुपए की लागत से पावर ग्रिड द्वारा विकसित बीकानेर-भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। बीकानेर से भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में 8.1 गीगावॉट सौर ऊर्जा की निकासी में मदद करेगी।
- प्रधानमंत्री ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला नया कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों तक विस्तार के योग्य होगी।
- इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुनर्विकास कार्य में रेलवे स्टेशन की मौजूदा संरचना की विरासत स्थिति के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए फर्श और छत के साथ-साथ सभी प्लेटफार्मों का नवीनीकरण शामिल होगा।
- प्रधानमंत्री ने 43 किमी. लंबे चूरू-रतनगढ़ रेल-खंड के दोहरीकरण की भी आधारशिला रखी। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से रेल परिवहन-संपर्क बढ़ेगा और बीकानेर क्षेत्र से देश के बाकी हिस्सों तक जिप्सम, चूना पत्थर, खाद्यान्न और उर्वरक उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के अंतर्गत शोध व प्रशिक्षण सुविधा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23.50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। विभाग द्वारा कार्यक्रम की गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से शिक्षक विदेशों के 1 से 100 क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यू.एस) रैंक और भारत के 1 से 100 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 6 माह तक के लिये होंगे।
- शिक्षक उत्कृष्ट शैक्षणिक नीतियों एवं संचालित कार्यक्रमों से परिचित एवं प्रशिक्षित हो सकेंगे। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन एवं शोध को प्रोत्साहन मिल सकेगा।
- इससे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) की ग्रेडिंग में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति और मज़बूत होगी। राज्य में शोध का स्तर बढ़ेगा।
- इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा किया जाएगा। नोडल विभाग कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

जनसंपर्क अलंकरण समारोह

चर्चा में क्यों?

9 जुलाई, 2023 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सुधि राजीव की अध्यक्षता में राजस्थान पब्लिक रिलेशंस सोसायटी द्वारा जयपुर में आयोजित जनसंपर्क अलंकरण समारोह में जनसंपर्क सहित विभिन्न सेवाओं में अनुकरणीय कार्य करने वाली 24 विभूतियों को सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में की नोट स्पीकर पूर्व आईएएस मनोज कुमार शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने वाली 24 विभूतियों को शॉल ओढ़ाकर, प्रशस्ति पत्र, श्रीफल तथा स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
- इस समारोह में राजस्थान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को 'जनसंपर्क श्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ओर से बीएल स्वामी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- इनके अलावा राजस्थान आवासन मंडल के विशेषाधिकारी (मुख्यमंत्री) फारुख आफरीदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट तथा जाने-माने गजल गायक पद्मश्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को विशिष्ट अलंकरण प्रदान किये गए।
- इस अवसर पर उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, तिलक पालावत, स्वर्गीय गोवर्धन लाल पाराशर के प्रतिनिधि, स्वर्गीय कमलनयन शर्मा के प्रतिनिधि, डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, दिग्विजय डाबरिया, उम्मेद राज जैन, डॉ कृति भारती, आशीष जैन पीआरओ, श्वेता पचौरी, आकांक्षा पालावत पीआरओ, विनायक शर्मा, तरुण टाक, महेश कचोलिया, शैलेंद्र शर्मा, आशीष, अमन, हिमांशु पाटनी, रेखा चटर्जी, मनोज भारद्वाज, सीमा राज, चंद्रशेखर एपीआरओ, स्निग्धा शर्मा तथा लिपि सिंघल को भी सम्मानित किया गया।

फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना के लिये मिलेगा अनुदान

चर्चा में क्यों?

10 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के किसानों को फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना पर अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के लिये 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023-24 में 7609 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे के लिये 22.40 करोड़ रुपए तथा 2527 हैक्टेयर क्षेत्र में मसाला बगीचे के लिये 1.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- इसमें 17.24 करोड़ रुपए की राशि राज्य कृषक कल्याण कोष एवं 6.55 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वहन की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट में घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से किसानों को फल एवं मसाला बगीचे लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

जयपुर में बनेगा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जयपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक का महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय जल्द शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालय के भवन निर्माण के लिये 15.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
- इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। यह राशि अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष से व्यय होगी।
- यह आवासीय विद्यालय 200 विद्यार्थी क्षमता का होगा। यहाँ 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर वे डे-स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर सकेंगे।
- इस विद्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुख्यमंत्री की यह स्वीकृति अभिभावकों और बच्चों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के बढ़ते रूझान एवं आवश्यकता की दृष्टि से दी गई है। यह अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट-सवाई माधोपुर के गजेंद्र को मिला एक लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में पहले दिन सवाई माधोपुर ज़िले के गजेंद्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए की राशि मिली।

प्रमुख बिंदु

- कॉन्टेस्ट में नागौर ज़िले के महेंद्र को दूसरा स्थान मिला जिसमें उन्हें 50 हज़ार रुपए की धनराशि मिली। इसी प्रकार जालौर ज़िले के जितेंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त कर 25 हज़ार रुपए की राशि प्राप्त की। साथ ही प्रदेश के 100 प्रतिभागियों ने 1000 रुपए (प्रत्येक ने) के साथ प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त किया।
- उल्लेखनीय है कि सरकारी योजनाओं को प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुँचाने के संकल्प को साकार करते हुए राज्य सरकार ने यह अभिनव प्रतियोगिता आयोजित की है।
- यह प्रतियोगिता 6 अगस्त तक चलेगी। सभी इच्छुक प्रतिभागी अपने वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं।

नोट :

विभिन्न ज़िलों में बनेंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास- जयपुर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और जोधपुर में नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार विभिन्न ज़िलों में छात्रावास खोलने जा रही है। साथ ही जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी स्थापना सहित अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि 200 करोड़ रुपए करने और वर्ष 2022-23 में अनुमोदित प्रगतिरत कार्यों को कोष के तहत कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- इन 9 ज़िलों में बनेंगे 10 छात्रावास- जयपुर में किशनपोल (बालिका), दूदू, नागौर में कुचामन सिटी (बालिका), बारां, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 50-50 बेड के छात्रावास बनाए जाएंगे। इन छात्रावासों में कक्षा 9 से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे।
- जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास बनेगा। यह 100 बेड का होगा। इसमें विभिन्न ज़िलों से जयपुर में आकर कार्य करने वाली अल्प-पारिश्रमिक प्राप्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा। यहाँ अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। केंद्र में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। विद्यार्थियों और आमजन के प्रोत्साहन के लिये गोष्ठियाँ भी आयोजित हो सकेंगी।

राइट-टू-हेल्थ कानून के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि उक्त समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी।
- उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी.रविकांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन निदेशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहटटा, वित्त एवं कानून विभाग के एक-एक प्रतिनिधि को उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है।

राज्यस्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्यस्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने परिवार कल्याण से संबंधित प्रचार-प्रसार के पोस्टर-फ्लिप चार्ट सामग्री का विमोचन भी किया।
- उन्होंने परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िलों, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों सहित व्यक्तिगत कार्मिकों व संस्थानों को प्रमाण-पत्र व निर्धारित पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया।
- इस समारोह में संस्थागत पुरस्कारों की श्रेणी में झालावाड़ ज़िला प्रथम, हनुमानगढ़ ज़िला द्वितीय, प्रतापगढ ज़िला तृतीय तथा बूंदी ज़िला चतुर्थ स्थान पर रहा।
- पीपीआईयूसीडी निवेशन में झालावाड़ ज़िला प्रथम, सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली पंचायत समितियों की श्रेणी में भीलवाड़ा ज़िले की शाहपुरा पंचायत समिति प्रथम, राजसमंद पंचायत समिति द्वितीय, अजमेर ज़िले की पीसांगन पंचायत समिति तृतीय तथा कोटपूतली पंचायत समिति चतुर्थ स्थान पर रही।
- सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ग्राम पंचायतों में राजसंमद ज़िले की सलोदा ग्राम पंचायत प्रथम, अजमेर ज़िले की मोयणा ग्राम पंचायत द्वितीय, राजसमंद ज़िले की ग्राम पंचायत छापली तृतीय तथा भीलवाडा ज़िले की तसवारियाबासा ग्राम पंचायत चतुर्थ स्थान पर पुरस्कृत हुई।
- सरकारी चिकित्सालयों की श्रेणी में ज़िला अस्पताल नीमकाथाना, सवाई माधोपुर ज़िले की सीएचसी बौंली और अजमेर ज़िले की सिंघावल पीएचसी सर्वश्रेष्ठ रही।
- निजी चिकित्सालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर दौसा का श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल प्रथम, भीलवाड़ा का सीटी अस्पताल द्वितीय स्थान पर पुरस्कृत हुआ।
- एनजीओ की श्रेणी में एफआरएचएस इंडिया जयपुर तथा कोटा ज़िले का परिवार सेवा संस्थान सम्मान पाने में सफल रहा।
- इस अवसर पर व्यक्तिगत श्रेणी में भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया।

नोट :

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना' की अधिसूचना जारी होने पर इसके क्रियान्वयन की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के पेश बजट में इस योजना के संबंध में घोषणा की गई थी।
- 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'राज्य में महिलाओं, कामगार, विभिन्न वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है।
- इस योजना के तहत एक लाख लोगों को आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिये पाँच हज़ार रुपए की सहायता मिलेगी। योजना से राज्य में स्वरोज़गार के नवीन अवसर सृजित होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड, राजीविका एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प, केश कला के कामगार, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों एवं राजीविका, एनयूएलएम की महिलाओं, श्रम विभाग के चयनित कामगारों को स्वयं का रोज़गार प्रारंभ करने के उद्देश्य से आधुनिक आवश्यक किट, आधुनिक उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड एवं विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र धारक पात्र होंगे।
- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बोर्ड एवं विभाग को निश्चित संख्या में तय लक्ष्यों के अनुरूप आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को उनके नज़दीक ही आवासीय विद्यालयों में पढ़ने का अवसर देने के लिये तथा जनजाति क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान के लिये 7 आवासीय विद्यालय खोलने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिनके भवन निर्माण के लिये 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष प्रथम चरण में प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगामी वर्ष में द्वितीय चरण के तहत इनके निर्माण कार्य पर 71 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- आवासीय विद्यालय राज्य के पाली के सुमेरपुर, सवाई माधोपुर, भेड़ोली-बौली (सवाई माधोपुर), अजमेर के केकड़ी स्थित गिरवरा, जालोर, डूंगरपुर के चिखली, टोंक के देवली स्थित श्रीपुरा में खोले जाएंगे।
- इन सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 210 होगी।

प्रदेश में 50 पक्षीघरों का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये 50 पक्षीघरों के निर्माण के लिये 43.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ये पक्षीघर उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षीघर की तर्ज पर 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे।
- पक्षीघरों के निर्माण, पक्षियों के लिये भोजन एवं विदेशी पक्षियों के क्रय हेतु प्रति पक्षीघर 87 लाख रुपए का व्यय होगा। इस प्रकार कुल 43.50 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।
- इसी राशि में से एक-एक लाख रुपए से पक्षीघरों में कोकटियल (ऑस्ट्रेलियाई बर्ड), लव बर्ड तोता, बजरिगर (बुग्गी तोता), गिनी फाउल (चकोर मुर्गा) आदि पक्षी पेट शॉप्स से खरीदे जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में 50 पक्षीघरों के निर्माण की घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति में यह मंजूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से प्रदेश में पक्षियों को संरक्षण मिलने के साथ ही बीमार, असहाय एवं घायल पक्षियों का उपचार एवं संवर्द्धन किया जा सकेगा।

राज्य स्तरीय सेमिनार राज. पल्मोकोन 2023

चर्चा में क्यों ?

15 से 16 जुलाई, 2023 तक जयपुर के पार्क पैराडाइज में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार राज. पल्मोकोन 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान लंग राजस्थान पुस्तक का लोकार्पण हुआ।

प्रमुख बिंदु

- पार्क पैराडाइज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ गहन शोध करते हैं, इनके निष्कर्ष मानव स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सेमिनार से वैचारिक आदान-प्रदान होगा, जो चिकित्सा जगत के लिये बेहतर साबित होगा।
- उन्होंने कहा कि बीकानेर ने चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल विकास किया है। यहाँ का पीबीएम अस्पताल बीकानेर संभाग सहित आसपास के राज्यों के मरीजों के लिये उपयोगी साबित हो रहा है। यहाँ का कैंसर रिसर्च और कार्डियो वास्कुलर सेंटर मरीजों के लिये जीवनदायी बना है।
- आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सेमिनार समय-समय पर होने चाहिये, जिससे विशेषज्ञों के चिकित्सा से जुड़े अनुभव साझा किये का सकें।
- ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने कहा कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का इतिहास स्वर्णिम रहा है। यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने देश और दुनिया में बीकानेर का नाम रोशन किया है।
- उन्होंने कहा कि बीकानेर का आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर पंजाब और हरियाणा के मरीजों के लिये बेहद उपयोगी साबित हुआ है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देशभर की ऐतिहासिक और अनूठी योजना है इस योजना ने लाखों प्रदेशवासियों के दु:ख दूर किये हैं।
- सेमिनार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड डॉ. पी.आर. गुप्ता को दिया गया। वहीं डॉ. महेंद्र कुमार, डॉ. सी आर चौधरी, डॉ. सीतू सिंह को डॉ. एस.के. सरकार ओरीयेशन अवॉर्ड दिया गया।

नोट :

केंद्रीय कारागार अलवर में 'दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन'का कारागार मंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2023 को कारागार विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भँवर जितेंद्र सिंह ने कारागार विभाग के बंदियों को रोज़गार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर में लगाए गए पेट्रोल पंप 'दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन'का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- कारागार विभाग मंत्री जूली ने कहा कि कारागार विभाग एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. के सहयोग से केंद्रीय कारागार परिसर में 'आशाएँ'संस्था द्वारा इस पेट्रोल पंप का संचालन शुरू किया गया है जिसमें खुली जेल में रहने वाले अच्छे चाल-चलन वाले कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जेल के बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। वहीं खुली जेल में रहने वाले कैदियों को इन नवाचारों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों द्वारा ही किया जाएगा जिसकी निगरानी कारागार मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी।
- पूर्व केंद्रीय मंत्री भँवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कारागार विभाग की इस पहल से खुली जेल में रहने वाले बंदियों को उनकी योग्यतानुसार रोज़गार उपलब्ध होगा जो उनके और उनके परिवार के लिये ससम्मान जीवन यापन करने के साथ समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिये अहम कडी साबित होगा।

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट-2023 : पर्यटन मंत्री ने किया आरडीटीएम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2023 को राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना में उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में घरेलू पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। राजस्थान पर्यटन अपने पर्यटन उत्पादों, पर्यटन अनुकूल नीतियों, योजनाओं और नवाचारों के कारण देश के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशंस में से एक है।
- राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपनी रूरल टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जैसी दूरदर्शी पर्यटन नीतियों के साथ देश भर के राज्यों के लिये एक आदर्श है। यह पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है।
- उन्होंने कहा कि अब तक यूडी टैक्स और बिजली छूट जैसे क्षेत्रों में लगभग 1000 होटल इससे लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट फंड को भी 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और 5 माईस (MICE) सेंटर भी खुल रहे हैं।
- राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार की पहल के कारण वर्ष 2019 में 187 प्रोजेक्ट्स की तुलना में वर्ष 2022 में 4500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 14856 कमरों वाली 206 नई परियोजनाएँ पंजीकृत की गई हैं।
- वर्ष 2021 के दौरान 2.20 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022 में 10.87 करोड़ पर्यटक राजस्थान आए। एक वर्ष में पर्यटकों की संख्या में 8 करोड़ की वृद्धि राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

नोट :

- पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग लाभ के दायरे में अधिकतम संख्या में पर्यटन इकाइयों को शामिल करने का प्रयास किया गया है।
- राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में होटल, मोटल, 10 या अधिक कमरों वाले, रीको भूमि पर होटल संचालित पर्यटन इकाइयों, होटलों, आरटीडीसी और आरएसएचसी होटलों, केंद्र और राज्य सरकार के संग्रहालयों पर राजस्व विभाग व ज़िला कलेक्टर द्वारा रूपांतरण आदेश लागू किया है।
- राजस्थान न केवल पर्यटन बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी पसंदीदा डेस्टिनेशन है। राज्य में नये धार्मिक सर्किट भी विकसित किये जा रहे हैं।
- एफएचटीआर के अध्यक्ष अपूर्व कुमार ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य की मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित करने की भी सख्त ज़रूरत है और यही कारण है कि इस वर्ष मार्ट की थीम उपयुक्त रूप से सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई है।
- इस दौरान रीगल राजस्थान-सस्टेनेबिलिटी एंपावरिंग द फ्यूचर पर एक ट्रैवल पब्लिकेशन का भी विमोचन किया गया।
- उल्लेखनीय है कि आरडीटीएम का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष मार्ट की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई है।
- 16 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम में राजस्थान के 200 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन किया और पूरे भारत से 200 से अधिक डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया।
- दो दिनों के दौरान खरीदारों और विक्रेताओं के बीच 7 हजार से अधिक बी2बी संरचित बैठकें हुईं, जिन्होंने अपने 600 से अधिक पर्यटन उत्पादों जैसे होटल, मोटल्स, रिसॉर्ट्स, ईटरीज, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, एम्यूजमेंट पार्क आदि की कुशलता और क्षमता का प्रदर्शन किया।
- मार्ट में देश के लगभग सभी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि से बायर्स शामिल हुए।

प्रदेश में 11 मिलेट्स एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये 3 करोड़ 37 लाख रुपए का अनुदान

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 11 मिलेट्स एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये 3 करोड़ 37 लाख रुपयों की अनुदान सहायता दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- कृषि मंत्री ने बताया कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये किसी भी ज़िले से किसानों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। मिलेट्स एवं अन्य खाद्य सामग्री की प्रसंस्करण इकाइयों के लिये निजी कंपनियों के 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये 3 करोड़ 37 लाख रुपयों की अनुदान सहायता दी गई है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन की घोषणा की गई है।
- मिशन के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को उन्नत किस्मों के निःशुल्क बीज, सुक्ष्म पोषक तत्त्व एवं जैव कीटनाशी किट का अनुदानित दर पर वितरण, मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना पर अनुदान, बाजरा व अन्य मिलेट्स के संवर्धन, प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आदि प्रावधान किये गए हैं।
- ज्ञातव्य है कि रागी, कंगनी, सावां, चीना, कोदो, कुटकी फसलें मिलेट्स के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी पोषण गुणवत्ता के बारे में जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं।
- राज्य की बीज उत्पादक संस्थाओं, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के पास छोटे अनाजों जैसे रागी, कंगनी, सावां, चीना, कोदो, कुटकी के उन्नत बीज उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ही इन बीजों को विकसित करने के लिये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद से बीज मंगाए गए हैं।

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में कहा कि जोधपुर में स्थापित किया जा रहा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानक स्थापित करेगा। राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिये इस संस्थान की स्थापना की जा रही है।
- यह विश्वस्तरीय संस्थान डिजिटल वर्ल्ड में एक नई क्रांति साबित होगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार होंगे, जिन्हें दुनिया भर में रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- संस्थान आईटी क्रांति के सूत्रधार भारत रत्न स्व. राजीव गांधी के नाम से स्थापित किया जा रहा है।
- वर्तमान दौर में जहाँ साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और निवेश व बीमा जैसे कार्यों के लिये लोगों को विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता बढ़ रही है, इस संस्थान से डिजिटल ज्ञानयुक्त वित्तीय प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ तैयार होंगे।
- राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से संस्थान के लिये 672.45 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, जिसमें से 130 करोड़ की राशि व्यय भी की जा चुकी है। इसके लिये 97 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है।
- संस्थान में यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज उपलब्ध हो सकेंगे। यह संस्थान डिजिटल स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होगा, जहाँ सायबर एक्सपर्ट और डिजिटल एक्सपर्ट तैयार किये जाएंगे।
- साथ ही, संस्थान आईआईटी, एम्स के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। यहाँ का प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वायत्तशासी होगा।
- विदित है कि इससे पूर्व सदन ने विधेयक पर जनमत जानने के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिया।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से स्क्रीनिंग कर पात्र अस्थायी अध्यापकों को नियमित किया जा सकेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इससे पूर्व वर्ष 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश लाया गया था। बाद में इस अध्यादेश का प्रतिस्थापक विधेयक विधानसभा में पारित कराया गया।
- इस अध्यादेश एवं अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर संबंधित विश्वविद्यालयों की सेवा में स्थायी किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 से पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ अस्थायी शिक्षक/योग प्रशिक्षक 2008 के अध्यादेश में कवर होने से रह गए। अत: राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों एवं योग प्रशिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर स्थायी किये जाने का निर्णय लिया है।
- इसके लिये 2008 के आमेलन अधिनियम में अस्थायी शिक्षक की परिभाषा को संशोधित करने व मूल अधिनियम के द्वारा आमेलन हेतु निर्धारित 180 दिवस की अवधि में छूट देते हुए राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक-2023 लाया गया है।

प्रदेश के 36 विद्यालयों में 45 नवीन विषय होंगे प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के 36 विद्यालयों में 45 नवीन विषय शुरू करने तथा इन विषयों के अध्यापन के लिये आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के 36 विद्यालयों में से 27 में 1-1 विषय और 9 विद्यालयों में 2-2 विषय शुरू होंगे। इनमें जयपुर के 6, अलवर के 4, भरतपुर, दौसा, जालौर के तीन-तीन, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, नागौर के दो-दो, अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, करौली, सीकर, टोंक तथा उदयपुर एक-एक विद्यालय शामिल हैं।

नोट :

- इन विद्यालयों में नवीन विषयों की शुरुआत के लिये प्रति विषय स्कूल व्याख्याता का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। इस प्रकार कुल 45 पदों का सृजन होगा।
- इसके अतिरिक्त अलवर एवं उदयपुर के एक-एक विद्यालय में जीव विज्ञान विषय प्रारंभ किया जाएगा। इन विद्यालयों हेतु प्रयोगशाला सहायक के एक-एक पद का भी सृजन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 बजट में नवीन विषय प्रारंभ करने की घोषणा की थी।
- इस मंजूरी से विद्यार्थियों को अपने-अपने निवास के पास ही पसंदीदा विषय चुनकर पढ़ने के अवसर मिलेंगे।

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने तथा पुलिस को सशक्त बनाने के लिये लाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबित होंगे।
- विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के प्रावधान किये गए हैं, ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत एवं अग्रिम जमानत नहीं होने के भी प्रावधान किये गए हैं।
- संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राज्य में अपराध की प्रवृत्तियों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव आया है। आपराधिक गिरोहों ने शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचना देने वाले और हथियार आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर संगठित नेटवर्क स्थापित कर लिये हैं।
- ये संगठित गिरोह मुख्य रूप से कॉन्ट्रेक्ट किलिंग, व्यवसायियों को धमकी देकर फिरौती मांगने, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त हैं। ये गिरोह कानून और प्रक्रिया के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का लाभ उठाते हुए अपराध करने के लिये अभिरक्षा से रिहा भी हो जाते हैं। कुछ समय से इन अपराधियों ने जनता में डरावनी छवि बना ली है। इसलिये इन अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक कठोर कानून की यह विधेयक पूर्ति करेगा।
- इस अधिनियम की धारा-28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालयों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वहीं धारा-29 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है। इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। पूर्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में इस तरह के कानून लागू किये जा चुके हैं।
- इससे पूर्व जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 पारित

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये लाया गया है।

नोट :

- विधेयक पारित होने से 8 हज़ार 255 करोड़ 67 लाख 40 हज़ार रुपए की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सकेगी।
- इससे पूर्व विधानसभा ने अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2023-24 (प्रथम संकलन) को भी पारित की।
- प्रभारी मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने मांगों का उपस्थापन किया, जिसे सदन ने मुखबंद का प्रयोग कर पारित कर दिया।

राज्य में अब 19 ज़िलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड की सूची जारी

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को राजस्थान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड्स के संरक्षण एवं एकीकृत प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के 19 ज़िलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड्स की सूची जारी की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के बारां ज़िले मे सर्वाधिक 12 वेटलैंड्स होंगे।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के 19 ज़िलों के 44 वेटलैंड्स से राज्य में पारिस्थितिकीय तंत्र सुदृढ़ होगा एवं वन्यजीवों के लिये बेहतर खाद्य श्रृंखला उपलब्ध हो सकेगी। पृथ्वी की किडनी के रूप में पहचाने जाने वाले वेटलैंड्स प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन व शुद्धिकरण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में अब कुल 44 अधिसूचित आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) क्षेत्र होंगे, जिनके अंतर्गत बारां ज़िले में वेटलैंड्स एकलेरा सागर, कोटरापार तालाब, बेथाली डैम, हिंगलोत डैम, उतावली डैम, सेहरोल डैम, गरड़ा तालाब, नियाना तलाई, नाहरगढ़, तेजा जी की तलाई, पुष्कर तालाब, ल्हासी डैम शामिल हैं।
- बीकानेर ज़िला अंतर्गत देवी कुंड सागर एवं सूरसागर, बूंदी ज़िला के अंतर्गत नवल सागर लेक, चित्तौडगढ़ ज़िले में मंगलवाड़ तालाब, किशन कारेरी, बड़वई लेक, गंभीरी डैम, डूंगरपुर ज़िले में साबेला तालाब, जोधपुर ज़िला अंतर्गत कायलाना व सूरपुरा, कोटा के अंतर्गत पक्षी विहार कैनवास, किशोर सागर, हनोतिया, नागौर ज़िले में डीडवाना (खाल्दा), पाली ज़िले में लखोटिया तालाब एवं लोरडिया तालाब, राजसमंद ज़िला के अंतर्गत राज्यावास एवं राघव सागर वेटलैंड्स शामिल हैं।
- इनके अलावा सीकर ज़िले में रेवासा, टोंक ज़िले में बुद्धसागर, बीसलपुर, चंदलाई, मोतीसागर, गलवानिया, टोरडी सागर, उदयपुर ज़िले में मेनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, भीलवाड़ा ज़िले में चावंडिया, प्रतापगढ़ ज़िले में केसरियावाड़, सिरोही ज़िले में लाखेराव तालाब, अजमेर ज़िले में बड़ा तालाब, जालौर ज़िले में रनखार, झालावाड़ ज़िले में बड़बेला तालाब शामिल है।
- अधिसूचना के अनुसार आर्द्रभूमि क्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर रोक रहेगी तथा किसी भी प्रकार का नया उद्योग स्थापित करने एवं मौजूदा उद्योगों के विस्तार पर प्रतिबंध रहेगा।
- साथ ही ठोस, खतरनाक व ई-अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण एवं निष्कासन पर प्रतिबंध रहेगा। मछलियों एवं माइग्रेटरी पक्षियों को आमजन द्वारा दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध रहेगा। वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन के साथ क्रशिंग इकाइयों पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के शिकार पर प्रभावी रोक रहेगी।
- आर्द्रभूमि के क्षेत्र एवं क्षमता को कम करने वाली गतिविधियों सहित प्रदूषण उत्सर्जन करने वाली समस्त वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही किसी भी प्रकार की भूजल निकासी प्रतिबंधित होगी।
- अधिसूचना के अनुसार वेटलैंड्स क्षेत्र में मछली पालन, नावों का संचालन, डिसिल्टिंग, अस्थायी निर्माण, विशेष उद्देश्य के लिये पानी की निकासी की जा सकेगी।
- क्या होते है वेटलैंड (आर्द्रभूमि):
  - 'किडनी ऑफ द लैंडस्केप'एवं बायोलॉजिकल सुपरमार्केट'के नाम से पहचानी जाने वाली ऐसी नम एवं दलदली भूमि, जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरी रहती है।
  - वेटलैंड्स वो पारिस्थितिकीय तंत्र हैं, जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं।

नोट :

- इसके अलावा 'कार्बन अवशोषण'व 'भू-जल स्तर'मे वृद्धि जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम् योगदान देते हैं।

राजस्थान कारागार विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कारागार विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के लिये सुधारात्मक उपबंध, मूलभूत मानवाधिकारों के हक, उनके कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिये राजस्थान कारागार विधेयक-2023 लाया गया है।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में 129 वर्ष पुराना प्रशासन एवं प्रबंधन कारागार अधिनियम-1894 एवं 63 वर्ष पुराना राजस्थान बंदी अधिनियम-1960 प्रभावी है।
- इन अधिनियमों में समय-समय पर किये गए विभिन्न संशोधनों को एकजाई कर राजस्थान कारागार विधेयक-2023 लाया गया है। यह विधेयक बंदियों के साथ ही जेलों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये कार्य करेगा।
- कारागार मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा बंदी सुधार के लिये विभिन्न नवाचार किये जा रहे हैं, ताकि सजा पूरी होने के बाद उन्हें रोज़गार मिल सके। खुला बंदी शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम एवं जेलों में पेट्रोल पंप खोलना इस दिशा में किये गए महत्त्वपूर्ण नवाचार हैं। खुले शिविर के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश के लगभग 40 प्रतिशत खुले बंदी शिविर राजस्थान में हैं।

नोट :

- प्रदेश की जेलों में बंदियों द्वारा एलईडी बल्ब बनाये जा रहे हैं, जो बाजार से कम दाम पर उपलब्ध हैं। शीघ्र ही डूंगरपुर एवं झालावाड़ में नई जेलों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
- प्रदेश में जेलों में सुविधाओं का विस्तार तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रदेश की 96 प्रतिशत जेलों में वीसी के माध्यम से पेशी की सुविधा उपलब्ध है और जल्द ही शेष जेलों में भी यह सुविधा स्थापित कर ली जाएगी। साथ ही जेलों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक, पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण किये जा रहे हैं।
- इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित हो गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने कहा कि प्राधिकरण का बिल पास होकर एक्ट बन जाने से अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व पदयात्राएँ अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सकेंगे।
- विदित है कि राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश है, जहाँ मेले और उत्सव लोगों के पारंपरिक जीवन का प्रमुख आधार है और तेजी से बदलते सामाजिक मूल्यों में इनकी प्रासंगिकता ओर अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य मेला प्राधिकरण का गठन 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही किया था और अब इस प्राधिकरण का विधिवत् एक्ट बनवाकर राज्य के मेले व लोक उत्सवों को संरक्षित, सुरक्षित व विकसित होने का कानूनी कवच पहना दिया गया है।
- राज्य सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से जहाँ एक ओर प्रदेश में धर्म-अध्यात्म का सम्मान करते हुए श्रद्धालुओं की आस्था को बलवती होने का अवसर दिया है, वहीं राज्य की मेला संस्कृति को पल्लवित होने का सुरक्षित वातावरण भी प्रदान किया है।

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस विधेयक पर चर्चा के बाद अपना जवाब देते हुए कहा कि जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलने से पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को अपने निकट ही बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही 16 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है तथा दौसा, बूंदी, करौली, अलवर और हनुमानगढ़ ज़िलों में भी इसी वर्ष मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार तीन ज़िलों- जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में अपने वित्तीय संसाधनों से भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है।
- जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय को शीघ्र संचालित करने के लिये 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही पद भी सृजित कर दिये गए हैं।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें भी 750 से बढ़कर 3 हज़ार 230 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर चिकित्सक नियुक्त किये गए हैं।
- इससे पहले विधेयक को जनमत जानने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

नोट :

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि खेती एवं पशुपालन सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ाने की मंशा से यह विधेयक लाया गया है।
- उन्होंने कहा कि पशुधन को बचाने एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक से युक्त शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहाँ दो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। बीकानेर में स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 16 ज़िले होंगे, जबकि जोबनेर में स्थापित होने वाले नये विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र 17 ज़िलों का होगा।
- कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि राज्य में 5 लाख 66 हज़ार पशुधन एवं 1 लाख 46 हज़ार कुक्कुट संपदा है। भारत सरकार के नये आँकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है।
- इससे पहले विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

तीन दशक में सर्वाधिक बैठकें पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में 144वीं बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा की नवीं विधानसभा से लेकर अब तक की पंद्रहवीं विधानसभा तक तीन दशक में यह 144 बैठकें सर्वाधिक है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं विधानसभा में क्रमश: 95, 141, 143, 140, 119 और 139 बैठकें हुई थी।
- पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल देश की अन्य विधानसभाओं में भी चर्चा का विषय रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने सदन संचालन में बेहतर प्रदर्शन कर सूचीबद्ध सभी प्रश्नों पर प्रतिदिन प्रश्नकाल के नियत समय में चर्चा कराई। पंद्रहवीं विधानसभा के आठवें सत्र में लगभग प्रतिदिन ही सूचीबद्ध सभी प्रश्नों पर नियत समय में चर्चा हुई।
- डॉ. सी.पी. जोशी ने विधायकों और मंत्रीगण को भी प्रश्न करने और जवाब देने के विश्लेषण में आने वाली कठिनाइयों को भी सरलता से विश्लेषण करके मदद की।
- विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 15,17 व 28 फरवरी और 1,2,3 व 15 मार्च और 17,18 व 19 जुलाई को प्रश्नकाल में सभी प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

राजकीय महाविद्यालयों में मिलेगी कैंपस प्लेसमेंट सुविधा

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने हेतु 9.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, प्रथम चरण में 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम वर्ष में दो बार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किये जाएंगे।
- कैंपस प्लेसमेंट से पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में सुगमता होगी।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) पुणे, राष्ट्रीय जैव विज्ञान केंद्र, बैंगलोर एवं सेबी के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों का कौशल संवर्द्धन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कैंपस प्लेसमेंट सुविधा प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी।

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक मृत शरीरों की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए इनके धरना-प्रदर्शन में किये जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मृत शवों को रखकर धरना-प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिये विधिक में प्रावधान नहीं है, इसीलिये यह विधेयक लाया गया है।
- संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि वर्ष 2014 से 2018 तक इस तरह की 82 एवं वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएँ हुई हैं।
- इस विधेयक से लावारिस शवों की डीएनए एवं जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर डाटा संरक्षित भी किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी पहचान हो सके।
- संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार परिजन से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा शव का विरोध करने के लिये इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकेगी। साथ ही परिजन द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकेगा।
- शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि सिविल रिट पिटीशन आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने मृत शरीरों के शिष्टतापूर्वक दफन या अंतिम संस्कार के निर्देश प्रदान किए थे। इस निर्देशों की पालना में इस विधेयक में लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना और इन शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से आनुवंशिक जेनेटिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।
- इससे लावारिस शवों का रिकॉर्ड संधारित हो सकेगा और उनकी भविष्य में पहचान भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारिस शव मिले हैं।
- इससे पूर्व सदन ने जनमत जानने के लिये विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

नोट :

राज्यपाल ने एपिलेप्सी पर इकोन-2023 सम्मेलन का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इकोन-2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस वैज्ञानिक युग में भी इस बीमारी के लक्षणों से घबराकर लोग रोगी को अंधविश्वास के चलते झाड़ा दिलाने, ओझाओं के पास जाने आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, यह दुखद है।
- राज्यपाल ने मिर्गी के उपचार के साथ इसके संबंध में जागरूकता के अधिकाधिक प्रसार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिर्गी कोई लाइलाज रोग नहीं रह गया है। इसका यदि समयबद्ध उपचार होता है तो 80 प्रतिशत मामलों में रोगियों के दौरे बंद हो जाते हैं और वह सामान्य जीवनयापन कर सकते हैं।
- जीवनशैली में बदलाव करते हुए प्राकृतिक जीवनचर्या का पालन करते, पर्याप्त नींद, नियमित योगासन, व्यायाम, प्राणायाम आदि को अपनाते हुए संतुलित आहार लिया जाए तो व्यक्ति कई रोगों से बच सकता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है।
- राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी ने कहा कि नए चिकित्सकीय शोधों के आधार पर हुई प्रगति से रोगी पर मिर्गी रोगियों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिली है। इस बीमारी की दवाइयों और इलाज की लागत कम करने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जाने चाहिये।
- राज्यपाल ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के पचास वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया।

राजस्थान युवा महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2023 को प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित किये जा रहे राजस्थान युवा महोत्सव-2023 का शुभारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान युवा महोत्सव-2023 में युवाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी देखने को मिल रही है। महोत्सव के प्रथम चरण में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेंगी।

नोट :

- राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लाम्बा ने बताया कि बड़ी संख्या में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा इस आयोजन में भाग ले रहे हैं।
- आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभाओं का चयन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण व सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये तैयार करना एवं स्वावलंबी बनाना है।
- राज्य की लुप्तप्राय एवं दुर्लभ लोक कलाओं का संरक्षण-संवर्द्धन करना एवं प्रोत्साहन देना भी इस आयोजन का उद्देश्य है।
- इन महोत्सवों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं यथा- सामूहिक लोक गायन, सामूहिक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य (कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी), शास्त्रीय एकल गायन (हिंदुस्तानी), नाटक, चित्रकला, आशु भाषण, स्लोगन लेखन, कविता, शास्त्रीय वाद्य यंत्र (हारमोनियम, तबला, बांसुरी, गिटार, सितार, मृदंग, वीणा) वादन, फोटोग्राफी आदि का आयोजन किया जा रहा है।
- वहीं फड, मांडणा, भित्तिचित्र, रावणहत्था, खड़ताल, मोरचंग, भपंग, अलगोजा, रम्मत, लंगा-मांगणियार, कठपुतली आदि से संबंधित प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हो रही हैं।
- युवा महोत्सवों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं का करियर मार्गदर्शन भी किया जाएगा।
- महोत्सव के अंतर्गत 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ज़िला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् राज्य स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी।

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर ने वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के बकाया पुरस्कारों की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रांत के साहित्य को प्रोत्साहित, सम्मानित और संवर्द्धित करने के लिये स्थापित स्वायत्तशासी संस्थान राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर ने वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के बकाया पुरस्कारों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- अकादमी अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण की अध्यक्षता में हुई अकादमी संचालिका की बैठक में अनुमोदन पश्चात् इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है।
- उल्लेखनीय है कि अध्यक्षविहीन समय के बकाया पुरस्कारों को दिये जाने हेतु गत अगस्त में ही कार्यभार सँभालने वाले अकादमी के युवा अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण की मांग पर मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अशोक गहलोत एवं कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने स्वीकृति प्रदान की थी। उस स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया में आवेदन मांगे और प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन कर उक्त पुरस्कार घोषित किये गए हैं।
- देश के अकादमिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि गत वर्षों के बकाया पुरस्कारों की सरकार की स्वीकृति के बाद किसी अकादमी ने घोषणा की है, वरना अध्यक्षविहीन काल के पुरस्कार सदैव लंबित ही रह जाते थे।

नोट :

- राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इन पुरस्कारों के तहत प्रतीक चिह्न के साथ एक निर्धारित राशि भी सम्मान्य साहित्यकार को दी जाती है।
- अकादमी के मौजूदा प्रावधानों के तहत मीरा पुरस्कार के लिये 75 हज़ार रुपए, सुधींद्र पुरस्कार, रांगेय राघव पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार, शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार प्रत्येक हेतु 31 हज़ार रुपए और प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार के लिये 21 हज़ार रुपए की राशि अर्पित की जाती है।
- अकादमी अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण ने बताया कि अगस्त माह में ही एक भव्य समारोह आयोजित कर इन पुरस्कारों को अर्पित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के पुरस्कार

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	कृति
मीरा पुरस्कार	गोविंद माथुर (जयपुर)	मुड़ कर देखता है जीवन'(काव्य)
सुधींद्र पुरस्कार	भानु भारवि (जयपुर)	'रंग अब वो रंग नहीं'(काव्य)
रांगेय राघव पुरस्कार	संदीप मील (गांव पोसानी-सीकर)	'कोकिलाशास्त्र'(गद्य कथा)
देवराज उपाध्याय पुरस्कार	सदाशिव श्रोत्रिय (उदयपुर)	'कविता का पार्श्व'(आलोचना)
कन्हैयालाल सहल पुरस्कार	ओम नागर (अंता-बारा)	'निब के चीरे से'(डायरी)
देवीलाल सामर पुरस्कार	अशोक राही (जयपुर)	'विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण मिल गया'(नाट्य)
सुमनेश जोशी पुरस्कार	माधव राठौड़ (जोधपुर)	'मार्क्स में मनु ढूंढ़ती'(कहानी)
शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार	पंकज वीरवाल किशोर (सलंबूर)	(बाल साहित्य)

वर्ष 2020-21 के पुरस्कार

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	कृति
मीरा पुरस्कार	डॉ. आर.डी. सैनी (जयपुर)	'प्रिय ओलिव'(गद्य)
सुधींद्र पुरस्कार	गुलाम मोहियुद्दीन माहिर (बीकानेर)	'आतशे-कल्बो-जिगर'(गजल काव्य)
रांगेय राघव पुरस्कार	रीना मेनारिया (उदयपुर)	'बनास पार'(गद्य कथा)
देवराज उपाध्याय पुरस्कार	माधव नागदा (लालमादड़ी-नाथद्वारा)	'समकालीन हिन्दी लघुकथा और आज का यथार्थ'(आलोचना)
कन्हैयालाल सहल पुरस्कार	उमा (जयपुर)	'किस्सागोई'(विविध)
देवीलाल सामर पुरस्कार	राजकुमार बुनकर इंद्रेश (जयपुर)	–
सुमनेश जोशी पुरस्कार	ब्रिजेश माथुर (अजमेर)	–
शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार	पूरन सरमा (जयपुर)	'सद्भाव का उजाला'(बाल साहित्य)

वर्ष 2021-22 के पुरस्कार

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता	कृति
मीरा पुरस्कार	डॉ. पँजा शर्मा (जोधपुर)	'मोबाइल, पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ (गद्य)
सुधींद्र पुरस्कार	जितेंद्र कुमार सोनी (धन्नासर-हनुमानगढ़)	'रेगमाल'(काव्य)
रांगेय राघव पुरस्कार	दिनेश पंचाल (विकासनगर, डूंगरपुर)	'खेत'(गद्य)

नोट :

देवराज उपाध्याय पुरस्कार	ओड़िसा प्रवासी दिनेश कुमार माली (सिरोही)	'त्रेतारू एक सम्यक् मूल्यांकन' (आलोचना)
कन्हैयालाल सहल पुरस्कार	विमला भंडारी (सलंबूर)	'अध्यात्म का वह दिन' (यात्रा-संस्मरण)
देवीलाल सामर पुरस्कार	प्रबोध कुमार गोविल (जयपुर)	'बता मेरा मौतनामा'
सुमनेश जोशी पुरस्कार	अश्विनी त्रिपाठी (बारां)	'हाशिये पर आदमी'(गज़ल)
शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार	सत्यनारायण व्यास (रायपुर-भीलवाड़ा)	'रोचक बाल कहानियाँ'(बाल साहित्य)

राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिये विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य विधानसभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक-2023 पारित किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिये विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सौगात दी है। इन गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण कर अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- इस विधेयक के माध्यम से बनने वाले अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा।
- यह बोर्ड प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। साथ ही पंजीकृत गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिये योजनाओं को मॉनिटर करने के साथ ही ऐसी योजनाओं के प्रशासन के लिये राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
- बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं के अनुसार फायदों तक गिग वर्कर्स की पहुँच हो और उनके कार्य करने की स्थिति बेहतर हो। यह बोर्ड गिग वर्कर्स के अधिकारों से संबंधित शिकायतों और अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों का समयबद्ध निवारण भी सुनिश्चित करेगा।
- गिग वर्कर्स के पंजीकरण के लिये एग्रीगेटर अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों में गिग वर्कर्स का डेटा बेस राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार एग्रीगेटर्स का रजिस्टर अपने वेब पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।
- इस अधिनियम से गिग वर्कर्स को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा और उनकी शिकायतों पर उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा।
- गिग वर्कर्स का बोर्ड में प्रतिनिधित्व भी होगा, जिससे वे उनके कल्याण के लिये लिये जाने वाले निर्णयों में भाग ले सकेंगे। अधिनियम के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिये शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसके समक्ष व्यक्तिश: अथवा ऑनलाइन माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी।
- वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कम कौशल वाले युवाओं के लिये गिग कार्य से रोज़गार की व्यापक संभावनाएँ हैं। अर्थव्यवस्था और रोज़गार में बड़े योगदान के बावजूद गिग वर्कर्स अभी तक श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह संरक्षण नहीं मिल पाता है। इस अधिनियम से गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिये गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की थी।

नोट :

राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का हुआ गठन

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोधी (लोधा) समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने, मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के लिये राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त/निदेशक/शासन सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड में सचिव का कार्य करेंगे।
- इसके अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अथवा उनका प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बोर्ड के लिये प्रशासनिक विभाग होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्व में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
- इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य लोधी (लोधा) समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करना, वर्तमान में संचालित विभिन्न जनकल्याकारी योजनाओं के बारे में विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये सुझाव देना है। यह बोर्ड समाज के परंपरागत व्यवसायों को नवीन तकनीक से लाभदायक स्थिति में लाने के सुझाव भी देगा।

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 अगस्त, 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक पत्र लिखकर कानून की समीक्षा करते हुए इसमें गैर-अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश प्रदान किये थे।
- इसकी अनुपालना में राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1952 को संशोधित करते हुए राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 विधेयक लाया गया है।
- इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

राजस्थान स्टेट गैस ने लागू की स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण नीति

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस (आरएसजीएल) के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल ने अपने कार्यालय परिसरों, अधिकृत भौगालिक क्षेत्रों के सीएनजी स्टेशनों, शहरी गैस वितरण परियोजना क्षेत्र के साथ ही व्यवसाय कार्यान्वयन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण (एचएसई) नीति का क्रियान्वयन शुरू किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल द्वारा जयपुर, कोटा, नीमराणा, कूकस, ग्वालियर और श्योपुर में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। दो मदर स्टेशन सहित 11 सीएनजी स्टेशन संचालित किये जा रहे हैं।
- आरएसजीएल के सभी कार्मिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके साथ ही नीति क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही ऑडिट की व्यवस्था भी होगी।
- आरएसजीएल की एचएसई नीति के सफल क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी संस्थान के सभी स्तर के कार्मिकों को सौंपी गई है। इसके साथ ही नीति में आवश्यकतानुसार सुधार व समयानुकूल बदलाव की व्यवस्था की गई है।
- आरएसजीएल की एचएसई नीति के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र में हानि के स्तर को भी न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।

जेजेएम में अब तक 5.40 लाख एफएचटीसी जल कनेक्शन में चौथे एवं व्यय में दूसरे स्थान पर राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक कुल 5 लाख 40 हज़ार जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर पहुँच गया है। साथ ही, अभी तक जेजेएम में 17 हज़ार 578 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,902 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में जल भवन में हुई जेजेएम की समीक्षा बैठक में ये आँकड़े सामने आए। बैठक में बताया गया कि मिशन के तहत अभी तक 44 लाख 49 हज़ार जल कनेक्शन हो चुके हैं।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभिन्न रीजन की अलग से वीसी कर एफएचटीसी की प्रगति की समीक्षा करने एवं विशेषकर उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर ज़िलों में एफएचटीसी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये।

नोट :

- उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जनवरी से मार्च 2023 तक तीन महीनों में प्रदेश में 7 लाख 34 हज़ार 715 जल कनेक्शन किये गए थे। इस वित्तीय वर्ष में भी यही गति बरकरार रही तो राजस्थान जल कनेक्शन के मामले में काफी ऊपर आ जाएगा।
- बैठक में जल गुणवत्ता परीक्षणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डॉ. अग्रवाल ने जीवाणु प्रदूषित एवं रसायनिक स्रोतों के उपचारात्मक उपाय, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, घरेलू जन कनेक्शनों के साथ ही ग्रामवार जल स्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण, महिलाओं ने एफटीके प्रशिक्षण आदि के बारे में जानकारी ली।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इस अवसर पर कहा कि ऋण के लिये अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी।
- उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 50 हज़ार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हज़ार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है।
- उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से फेच किया जाता है।
- इस अवसर पर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि अनुजा निगम एक चैनेलाइजिंग एजेंसी है, जिसका प्रमुख कार्य राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्तजन एवं सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का आर्थिक विकास एवं उनकी उन्नति में सहायता करना है, ताकि इन वर्गों के सदस्यों का जीविकोपार्जन सही ढंग से हो सके तथा उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार हो सके।

नोट :

राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिये 'राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड'के गठन का आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- यह बोर्ड तेली समुदाय के लोगों के उत्थान के लिये नवीन योजनाएँ बनाकर तथा समस्याओं की पहचान कर राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा।
- बोर्ड तेली घाणी के संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ ही युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्द्धन, रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने, बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करने तथा विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग सहित अन्य कार्य करेगा।
- बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों सहित कुल 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
- इसके साथ ही उद्योग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम एवं रोज़गार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन, सचिव/शासन सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के विभागीय अधिकारी), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी, राजस्थान स्वर्ण कला विकास बोर्ड सचिव इस बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। वहीं कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा।

नोट :

प्रदेश के 246 राजकीय विद्यालय होंगे अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 246 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अजमेर के 13, अलवर के 20, बारां के 7, बाड़मेर के 6, भरतपुर के 10, बीकानेर के 8, चित्तौड़गढ़ के 3, दौसा के 12, धौलपुर के 8, डूंगरपुर के 5, गंगानगर के 7, हनुमानगढ़ के 11, जयपुर के 32, जालौर का 1, झुंझुनूं के 12, जोधपुर के 20, करौली के 5, नागौर के 18, राजसमंद के 8, सवाई माधोपुर के 13, सीकर के 8, टोंक के 12 तथा उदयपुर के 7 राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किये जाएंगे।
- इन विद्यालयों में 57 प्राथमिक, 125 उच्च प्राथमिक तथा 64 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठ सकेगा तथा क्षेत्र के विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर ही अंग्रेजी माध्यम में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदेश में 3 उपखंड, 7 तहसील और 20 नवीन उप तहसीलों का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन की आमजन तक पहुँच आसान बनाने के लिये प्रदेश में 3 उपखंड, 7 तहसील और 20 उप तहसील कार्यालयों के गठन को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार प्रदेश में नवीन प्रशासनिक इकाइयों का गठन कर रही है। इससे आमजन को राजकीय कार्य कराने में आसानी होगी। साथ ही इकाइयों से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा और क्षेत्र विकास को गति मिलेगी।
- जोधपुर के बापिणी, जयपुर के किशनगढ़-रेनवाल तथा रामपुरा डाबड़ी में नवीन उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न ज़िलों की 6 उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत तथा 1 नवीन तहसील का गठन किया जा रहा है।
- इनमें दौसा के कुंडल, धौलपुर के बसई व नवाब, डूंगरपुर के ओबरी, जोधपुर के चामूं, कोटा के चेचट तथा उदयपुर के फलासियां उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। उदयपुर के घासा में नवीन तहसील कार्यालय भी खोला जाएगा।
- अलवर के हरसोरा, बाड़मेर के सवाउ पदमसिंह, पादरू, लीलसर व भियाड़, बांसवाड़ा के छोटी सरवा, बारां के रेलावन, बीकानेर के दामोलाई मय राणेर, भीलवाड़ा के अंटाली, डूंगरपुर के सरोदा, धौलपुर के कोलारी, जोधपुर के पीलवा, करौली के शेरपुर, जालौर के खासरवीर, नागौर के गोटन, पांचौड़ी व मिठड़ी, प्रतापगढ़ के धमोतर तथा उदयपुर के खेरोदा व कनबई में नवीन उप तहसील खोली जाएंगी।

राज्यपाल ने राज्य सरकार के अधिसूचना प्रस्तावों को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के विभिन्न अधिसूचना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा।
- संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिये जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है।

नोट :

- इसी तरह राज्यपाल ने शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।
- राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भाँति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत 'रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स'के उपनियम चार में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी, 2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

प्रदेश के 28 ज़िलों में खुलेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये अब ज़िला मुख्यालयों में आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश के 28 ज़िलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल निर्माण के लिये 78.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिये 84 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन हॉस्टल में 50-50 आवासीय क्षमता होगी।
- गौरतलब है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा युवा आवास पूर्व से ही संचालित हैं। अत: शेष 28 ज़िलों में हॉस्टल शुरू होने से सभी ज़िलों के युवाओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

कोटा में तैयार हुआ दुनिया का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- कोटा में बना यह हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जो कि चंबल नदी के दोनों किनारों पर बेहद खूबसूरत तरीके से 6 किमी. तक बनाया गया है।
- चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण करवाया गया है। इन घाटों को अलग-अलग थीम पर तैयार किया गया है।
- चंबल रिवर फ्रंट से चंबल नदी के किनारे बसी बस्तियों को बाढ़ से निजात मिलेगी, साथ ही चंबल नदी में गिर रहे 14 गंदे नालों को ट्रैप कर नाले के पानी को एसटीपी से फिल्टर ट्रीटमेंट किया गया है, जिससे के चंबल के पानी का शुद्धिकरण भी होगा।
- चंबल रिवर फ्रंट पर बने वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व के अलग-अलग देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतें और वास्तुकलाओं को बनाया गया है। जिस तरह किशोर सागर तालाब के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाया गया है, जहाँ पर देश-दुनिया के सात अजूबे बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर रिवर फ्रंट के वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व की नौ प्रसिद्ध इमारतों की कलाकृति का निर्माण किया गया है।
- करीब 240 मीटर क्षेत्र में एक के बाद एक कतार से यह वास्तुकलाएँ बनाई गई है, जिसमें भारत की शान लाल किला, गोपुरम् टैंपल, चाइनीज पगोड़ा, हिस्ट्री पार्क, वेस्ट मिंस्टर, टेवी फाउंटेन, वारम टैंपल, मास्क्यू और लॉवरे म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे।

नोट :

- यूआईटी के विशेष अधिकारी आरडी मीणा ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट देश और दुनिया में कोटा के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आगामी अगस्त में चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होगा। इसके बाद इसे पर्यटकों के लिये खोल दिया जाएगा।
- यहाँ चंबल नदी के किनारे देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बनाई गई है तो वहीं भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन भी पर्यटक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति और विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी चंबल किनारे चंबल रिवर फ्रंट पर पर्यटकों को देखने को मिलेगी।
- आरडी मीणा के मुताबिक, रिवर फ्रंट पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी बनाया गया है। इस फेस मास्क के पीछे की तरफ से लोग मास्क के अंदर जा सकेंगे और इनकी आंखों से रिवर फ्रंट का नजारा देख सकेंगे। रिवर फ्रंट पर वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बैराज गार्डन को भी विकसित किया गया है।
- आरडी मीणा ने बताया कि बार्सिलोना फाउंटेन की तर्ज पर यहां भी फाउंटेन बनाया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक रंग बिरंगी रोशनी और म्यूजिक के साथ फाउंटेन शो एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा मुकुट महल में संग्रहालय बनाया जा रहा है।
- रिवर फ्रंट में योग की मुद्रा में एक इनविजिबल स्ट्रक्चर है, जिसे दोनों तरफ (राइट और लेफ्ट) से देखने पर ही नज़र आएगा, लेकिन सामने से देखने पर यह गायब हो जाता है। इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है।
- इसके अलावा यहाँ पर देश का पहला एलईडी गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ आने वाले लोगों को वास्तविक पेड़-पौधे पक्षियों की जगह एलईडी एलिमेंट दिखाई देंगे। रिवर फ्रंट के पूर्वी जोन में जोडियक घाट भी विकसित किये गए हैं, जिसमें अलग-अलग राशि चक्र हैं।
- कि रिवर फ्रंट पर थाई टैंपल की खूबसूरत हूबहू इमारत बनाई गई है। यहाँ पर छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं, जिनमें लाल किला भवन में मुगलई, गोपुरम् भवन में साउथ, चाइनीस बिल्डिंग में चाइनीस व्यंजनों का भी पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे।
- यहाँ पन्नाधाय हाडी रानी का शौर्य भी दिखेगा तो पूर्वी छोर पर हाडौती घाट बनाया गया है। बूंदी शैली पर निर्माण की 84 खंभों की छतरी तारागढ़ फोर्ट भी बनाया गया है। रिवर फ्रंट पर बच्चों के लिये भी खास किड्स जोन में वाटर पार्क म्यूज़िकल जोन भी बनाया गया है।
- यहाँ कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ भी दे सकेंगे और लोग बैठकर सुन सकेंगे। साथ ही 5 साहित्यकारों की प्रतिमा भी लगाई गई हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें आने वाले पर्यटक किताबें पढ़ सकेंगे।
- आरडी मीणा के मुताबिक, रिवर फ्रंट पर अलग-अलग तरह के फव्वारे होंगे, जबकि सिंह घाट में 9 शेर व्हाइट मार्बल से लगाए गए हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर एक छोटा सा बाजार भी रहेगा और यहाँ बोटिंग और क्रूज का भी संचालन होगा।

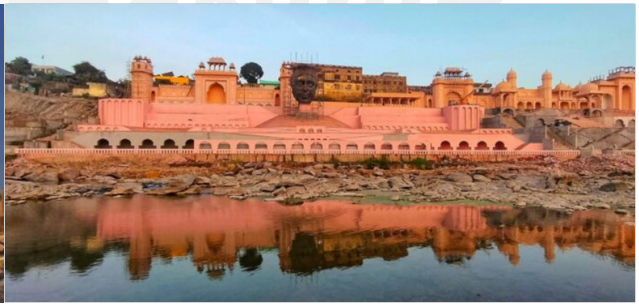

नोट :

प्रदेश में 15 अल्पसंख्यक राजकीय आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये राज्य में 15 स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी।
- जानकारी के अनुसार अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के रमजान की गफन (चौहटन) और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिये, जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामां, जोधपुर के जेतडासर (बाप), जैसलमेर के नाचना (पोकरण) में बालकों के लिये राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।
- प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह आवासीय विद्यालय 100 विद्यार्थी क्षमता के होंगे तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थी होने पर उन्हें डे-स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।

प्रधानमंत्री ने सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र समर्पित करते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने किसानों को लाभान्वित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम में 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) राष्ट्र को समर्पित किये। सभी किसानों की ज़रूरतों के लिये वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिये पीएमकेएसके विकसित किये जा रहे हैं।
  - कृषि इनपुट (उर्वरकों, बीजों, उपकरणों) की जानकारी से लेकर मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिये परीक्षण सुविधाओं तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक पीएमकेएसके को देश में किसानों के लिये एक विश्वसनीय समर्थन प्रणाली बनाने की परिकल्पना की गई है।
  - वे ब्लॉक/ज़िला स्तर के विक्रय केंद्रों पर उर्वरक खुदरा विक्रेताओं का नियमित क्षमता निर्माण भी सुनिश्चित करेंगे।
- प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड की एक नई किस्म का शुभारंभ किया, जो सल्फर के साथ लेपित है। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी।
  - यह अभिनव उर्वरक नीम-लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है, पौधों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करता है, उर्वरक की खपत को कम करता है और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
- प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) से 1600 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को जोड़ने की शुरुआत की। ओएनडीसी एफपीओ को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस-टू-कंज्यूमर लेनदेन तक सीधी पहुँच के साथ सशक्त बनाता है और स्थानीय मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहित करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स के विकास को उत्प्रेरित करता है।
- प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त की राशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी की।
- प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में पांच नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और बाराँ, बूंदी, करौली, झुंझुनूँ, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी।
  - मेडिकल कॉलेजों की स्थापना वर्तमान ज़िला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये केंद्र प्रायोजित योजना के तहत की जा रही है।
  - प्रधानमंत्री ने जिन पाँच मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, उन्हें 1400 करोड़ रुपए से अधिक की संचयी लागत से विकसित किया गया है, जबकि जिन सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी, वे 2275 करोड़ रुपए की संचयी लागत से बनाए जाएंगे।
  - 2014 तक राजस्थान में केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र सरकार के समर्पित प्रयासों के माध्यम से राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। यह 250 प्रतिशत की वृद्धि है।
  - इन 12 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2013-14 में 1750 सीटों से बढ़कर 6275 हो जाएगी, जो 258 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- प्रधानमंत्री ने इसके अतिरिक्त उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ज़िलों में छह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, जिससे इन ज़िलों में रहने वाली जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी। वह कार्यक्रम के दौरान जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय, तिंवरी का भी उद्घाटन किया।

नोट :

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में छह ईएमआरएस का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के उदयपुर ज़िले में दो, बांसवाड़ा में दो, प्रतापगढ़ में एक और डूंगरपुर में एक कुल मिलाकर छह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रत्येक स्कूल की क्षमता 480 छात्रों की है, जिनमें 240 लड़कियाँ होंगी। इन स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिये अलग-अलग छात्रावास, कर्मचारियों के लिये आवास, भोजन का स्थान और खेल का मैदान होगा।
- इन स्कूलों का निर्माण मैदानी क्षेत्रों में 38 करोड़ रुपए और पहाड़ी इलाकों में 48 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
- इन स्कूलों के निर्माण से 2880 आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे, जिनमें आधी लड़कियाँ होंगी।

एक नजर में राजस्थान के आँकड़े:		
योजना/शुरुआत	**2013-14**	**2022-23**
स्वीकृत विद्यालय	8	31

- राजस्थान में 31 ईएमआरएस स्वीकृत हैं जिनमें उदयपुर में आठ, बांसवाड़ा में छह, डूंगरपुर में चार, प्रतापगढ़ में चार, अलवर में दो, जयपुर में दो टोंक में एक करौली में एक, बारा में एक] सिरोही में एक, सवाई-माधोपुर में एक शामिल हैं। (संख्या में आँकड़े स्कूलों की संख्या दर्शाते हैं) A 31 में से 24 स्कूलों में निर्माण पूरा हो चुका है और 7 स्कूल निर्माणाधीन हैं, जिनके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

आँकड़े एक नज़र में- अखिल भारतीय		
योजना/शुरूआत	**2013-14**	**2023-24**
बजट परिव्यय	**278.76** करोड़ रुपए (संविधान के अनुच्छेद **275(1)** के तहत एक घटक के रूप में	**4000** करोड़ रुपए (पृथक् केंद्रीय क्षेत्र योजना)
स्वीकृत विद्यालय	167	693
कार्यात्मक विद्यालय	119	401
आवर्ती लागत	**42,000** रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष	**1,09,000** रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष
पूंजी लागत	**12.00** करोड़ रुपए (मैदानी क्षेत्र) **16** करोड़ रुपए (पहाड़ी, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद)	**37.80** करोड़ रुपए (मैदानी क्षेत्र), **48** करोड़ रुपए (पहाड़ी, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद)
सीबीएसई से संबद्ध स्कूल	69	277
नामांकन	34365	113275

- वर्तमान में 8,925 छात्र पढ़ रहे हैं और जब सभी स्कूल पूरे हो जाएंगे तो इन स्कूलों में 14,880 छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे।
- ईएमआरएस से लाभ पाने वाली प्रमुख जनजातियों में भील, गमेती, गरासिया, मीना, सहरिया शामिल हैं।
- 5 करोड़ की लागत से पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत सड़क निर्माण और पेयजल के लिये भी धनराशि दी जा रही है।
- प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं। ये एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल ऐसे प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ 50 प्रतिशत या 20,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है।

नोट :

- ईएमआरएस के निर्माण की लागत 2021-22 में 452 नए स्कूलों के लिये मैदानी क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 24 करोड़ रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए कर दी गई थी। अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- विदित है कि वर्ष 2013-14 में 167 स्कूल स्वीकृत किये गए थे, जो आज बढ़कर 693 हो गए हैं तथा 2013-14 में 119 स्कूल क्रियाशील थे, जबकि वर्तमान में 401 स्कूल क्रियाशील हैं। पिछले 5 वर्षों में 110 स्कूलों में निर्माण पूरा हुआ है।

राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह बोर्ड गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (गवाला), पूर्बिया (धनगर, गाडरी) जाति वर्ग की स्थिति का जायज़ा लेकर, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
- बोर्ड द्वारा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, रोज़गार को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराइयों/कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने और परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने सहित अन्य सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।
- इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक/संयुक्त निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे।
- इनके अलावा, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

नेवटा बांध और कानोता बांध बनेगा ईको एडवेंचर टूरिज़्म साइट

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब ईको एडवेंचर टूरिज़्म साइट के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार नेवटा और कानोता बांध में विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
- जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग 2.48 करोड़ रुपए की लागत से बर्ड वाचिंग प्लेटफॉर्म, छतरी का निर्माण, 600 मीटर लंबी पैरापेट दीवार सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण किये जाएंगे।
- नेवटा बांध पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। यहाँ प्रवेश द्वार से बांध की तरफ जाने वाला मार्ग भी बनाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

'प्रसव वॉच'एप्लीकेशन को मिला 'नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवॉर्ड'

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली स्थित स्थानीय होटल में आयोजित 'नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव'में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की 'प्रसव वॉच'एप्लीकेशन को चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिये 'नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवॉर्ड'से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान की ओर से यह सम्मान राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के प्रतिनिधि के रूप में आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और परियोजना निदेशक डॉ. तरुण चौधरी ने ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा राज्य की प्रमुख उच्च प्रसवभार वाले 360 मेडिकल इंस्टीट्यूट पर करवाए जा रहे संस्थागत प्रसवों की डिजिटलाइज क्लिनिकल केयर और मॉनिटरिंग के लिये 'प्रसव वॉच'एप्लीकेशन संचालित की जा रही है।
- इसके माध्यम से इन चिकित्सा संस्थानों पर हो रहे प्रसवों के लिये की गई क्लिनिकल केयर एवं प्रॉसिजर्स की ड्यूटी स्टाफ/डॉक्टर द्वारा रियल टाइम डेटा एंट्री प्रसव कक्ष एवं पीएनसी वार्ड में उपलब्ध करवाए गए टेबलेट पर की जाती है।
- इस एप्लीकेशन पर क्लिनिकल डेटा फीड करते समय सजेस्टीव मैसेज भी अलर्ट के रूप में संबंधित स्टाफ को रियल टाइम प्रदर्शित होते हैं, जिसमें यह शामिल होता है कि किस तरह की जटिलता होने की संभावना है एवं उसका निदान करने के लिये क्या संभावित कदम उठाए जाने हैं।

नोट :

देवस्थान विभाग व आईआरसीटीसी के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2023 के तहत उद्योग भवन में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में देवस्थान विभाग एवं आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू साइन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- देवस्थान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप एवं उनके विजन को मूर्त रूप देते हुए यह एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के साइन होने से 28 जुलाई से नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन हेतु जाने वाले वरिष्ठ नागरिक-नागरिकों को सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी।
- उन्होंने बताया कि जयपुर से दिल्ली की यात्रा आईआरसीटीसी के ज़रिये बस से संपन्न होगी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वरिष्ठ नागरिक अपनी हवाई यात्रा शुरू करेंगे एवं काठमांडू पहुँचकर पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे।
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के सपने को राज्य सरकार रेल यात्रा एवं हवाई यात्रा के ज़रिये पूरा कर रही है। इस योजना में निरंतर नवीन तीर्थ स्थलों को भी सम्मिलित किया जा रहा है।
- 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही यह यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी तथा प्रतिदिन 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा पर जाएंगे। श्री गंगानगर ज़िले के 100 यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन यात्रा के लिये काठमांडू जाएंगे।
- इस वर्ष योजना के तहत 40000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 36000 यात्री रेल यात्रा एवं 4000 हवाई यात्रा से दर्शन कर पाएंगे।

'मिशन वात्सल्य योजना' का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने शासन सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटक्शन सोसायटी की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 'मिशन वात्सल्य योजना' का अनुमोदन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य एवं प्रत्येक ज़िला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा।
- बैठक में सामूहिक फोस्टर केयर, व्यक्तिगत फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया है।

नोट :

- बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव ने बताया कि उपेक्षित बालक-बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह अब पारिवारिक देखरेख के अंतर्गत पालन-पोषण देखरेख उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 28 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार प्रदेश में लोक कलाओं का संरक्षण करने तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में ये मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023 के अंतर्गत वितरित किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की थी।
- इस योजना में लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र-उपकरण क्रय करने के लिये 5 हज़ार रुपए राशि की एकबारीय आर्थिक सहायता देय है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघिन टी-111 के तीन शावकों का हुआ नामकरण

चर्चा में क्यों ?

- 29 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन टी-111 के 2 वर्ष के हो चुके तीन शावकों (2 बाघ एवं 1 बाघिन) का नामकरण करने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

- इन शावकों के नाम क्रमश: चिरंजीवी, चिरायु एवं अवनी रखे गए हैं।

नोट :

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया के नाम पर बाघिन टी-19 का नामकरण कृष्णा किया गया था।
- इसी प्रकार अब पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा के नाम पर शावक का नाम अवनी रखने का निर्णय लिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि देश में जब बाघ विलुप्ति की कगार पर थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरुआत की। इससे देश में बाघों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले 1 माह में रणथंभौर नेशनल पार्क में 6 शावकों ने जन्म लिया है।

जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में आरती, मनीष और किरण ने जीते नकद पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2023 को जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के परिणाम घोषित किये गए, जिसमें आरती, मनीष और किरणजीत ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर नगद पुरस्कार प्राप्त किये।

प्रमुख बिंदु

- यह वीडियो दो सोशल मीडिया हैंडल पर 'JanSammanJaiRajasthan' के साथ शेयर हो रहे हैं। उचित मापदंडों के आधार पर वीडियो की जाँच-परख के बाद पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि 27 जुलाई, 2023 को यह कॉन्टेस्ट आयोजित हुआ था, जिसके परिणाम आज जारी किये गए, जिसमें जोधपुर की आरती सोनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए जीते।
- वहीं दूसरे स्थान पर रतनगढ़, चूरू के मनीष शंकोलिया रहे। उन्होंने 50 हज़ार रुपए की ईनामी राशि प्राप्त की।
- इसी प्रकार संगरिया, हनुमानगढ़ की किरणजीत कौर ने 25 हज़ार की राशि जीत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- इसके अलावा 100 लोगों को एक-एक हज़ार रुपए के प्रेरणा पुरस्कार भी प्रदान किये गए।
- गौरतलब है कि जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिये पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं के प्रचार-प्रसार को गति मिल रही है। साथ ही समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी योजनाओं की जानकारी और लाभ मिल रहा है।

राजस्थान को मिला बेस्ट कल्चरल टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2023 को अपनी कला संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिये विशेष पहचान रखने वाले राजस्थान को एक और पुरस्कार से नवाजा गया। बंगलुरू में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे पर्यटन विभाग को बेस्ट कल्चरल टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवॉर्ड से नवाज़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट बंगलुरू में आयोजित इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- इस आयोजन में राजस्थान पर्यटन के पवेलियन में राज्य की 14 ट्रैवल एजेंसीज़ और होटलियर्स ने भाग लिया।
- राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
- इसके साथ ही पवेलियन में पधारे स्थानीय ट्रैवल एजेंटों और आम जन को राजस्थान के पर्यटन स्थलों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

नोट :